[Dr. K. L. Rao]

may not concern the Bill, there are a lot of useful suggestions made in respect of the electricity situation in the country and they will receive very great attention from the Ministry of Irrigation and Power.

Mr. Chairman: We will now take up the half-an-hour discussion.

17.06 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION *RE*: GANDAK PROJECT

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैडम चेयरमैन, मैंने स्टार्ड क्वेश्चन 1653 ता० 12-5-66 को रखा था । प्रश्न मेरा यह था कि गण्डक योजना के कार्यान्वयन में रुपये-पैसे की कमी के कारण से देरी हो रही है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है । उसके बाद फखरुद्दीन साहब, जो यहां बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका जवाब मिला कि बिहार गवर्नमेंट ने 1966-67 में 9.18 करोड़ रुपया रखा है, केन्द्र सरकार ने इसके लिये तीन करोड़ रुपया दिया है और आगे इसके लिये यदि बिहार गवर्नमेंट अपने बजट में रुपया रखेगी तो काम होगा और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी इस में जो अनुदान होगा, इसके लिये खर्च करेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना—इसका बहुत पहले 20–22 करोड़ रुपये का अन्दाज़ लगा था, उसके बाद इसका अन्दाज़ा 36 करोड़ रुपये हुआ, 36 करोड़ के बाद 56 करोड़ रुपये हुआ और अब 56 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 124 करोड़ रुपये इसका तखमीना हो गया है । अब तक मैं समझता हूं कि इसमें कुल लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । इस समय जो खर्च की रफ़्तार है, फखरुद्दीन साहब ने जो जवाब दिया है, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो इस डिवैल्यूएशन के बाद जो मंहगाई हो गई है, उसको देखते हुए स्वाभाविक है कि इसका खर्च 150 करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा हो जाय । यह योजना सन् 1960 में मंजूर हुई थी और अब 1966 हो गया है, इन सात वर्षों में हम ने 20 करोड़ रुपया खर्च किया है । ऐसी स्थिति में, मैडम चेयरमैन, अन्दाजा लगा लीजिये कि जब कि इस योजना का तखमीना बढ़ता जा रहा है, कब तक यह पूरी हो सकेगी ।

हमारे यहां कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी पैसा लगाया जाय और जल्दी से जल्दी उसका रिटर्न मिले । रिटर्न जो हमारे यहां जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि हिन्दुस्तान की जितनी भी योजनायें हैं उनके मुकाबले में, हिन्दुस्तान के जितने भी विज्ञान-वेत्ता और बड़े बड़े इंजीनियर हैं और खुद हमारे डा० के० एल० राव साहब, जब वह खुद इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है । लेकिन जब वह मिनिस्टर हो गये तो न मालूम क्यों सुस्त हो गये, इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं । यही नहीं हमारे मिनिस्टर श्री फखरुद्दीन साहब, जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, जनसेवक हैं, इनके आने पर भी इस योजना का भाग्य ऐसा लगता है कि जो इस पर खर्च होता है, उसको देखते हुए 15-20 वर्षों से पहले हल नहीं हो पायेगी ।

इधर इसमें एक बात हुई है । राव साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि रुपये-पैसे की बड़ी दिक्कत है, इसलिये इसका इन्तजाम सोचना होगा, सरकार इसके लिये सोचेगी । इस पर हम लोग जो गण्डक-कमांडेड एरिया के लोग हैं, हम लोगों ने प्लानिंग मिनिस्टर साहब से मुलाकात की । उन बेचारों ने हमारे साथ बड़ी भलमनसाहत दिखलाई, उन्होंने फौरन दो आदमियों को इस काम के लिये लगा दिया—एक ठाकुर साहब और एक नाग साहब । ये दोनों सज्जन वहां गये, जहां पर यह योजना बन रही है, इन लोगों ने वहां जाकर देखा, हम लोग भी जो उस क्षेत्र के एम० पीज़ हैं, जैसे द्वारका नाथ तिवारी, कमल नाथ तिवारी, इन से जाकर मिले ।

एक माननीय सदस्य : भागवत झा आजाद नहीं गये थे ।

श्री विभूति मिश्र : वह नहीं गये थे, मैं झूठ नहीं कहूंगा । ये लोग वहां गये, बिहार के मिनिस्टर भी आये, उनके आफिस के लोग भी आये ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हम लोग सन्थाल परगने के हैं ।

श्री विभूति मिश्र : बातचीत के दौरान यह प्रकट हुआ कि प्लानिंग कमीशन जितना इस पर खर्चा आयेगा उसको देने के लिए तैयार है बशर्ते कि बिहार गवर्नमेंट की एजेंसी इसको कार्यान्वित करे । हम लोग इसके पहले जब पूछते थे तब बिहार गवर्नमेंट कहती थी कि सैंटर पैसा नहीं देता है और जब सैंटर से पूछते थे तो सैंटर कहता था कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, वह खर्च करने के लिए तैयार नहीं है । सैंटर स्टेट के ऊपर इसको डाल देता था और स्टेट सैंटर के ऊपर इसको डाल देती थी । इस बैठक के बाद यह तय हुआ कि सैंटर तो रुपया देना चाहता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं है कि इसको खर्च कर सके । वहां यह तय हुआ कि छः महीने के बाद फिर एक बैठक होगी और तब यह बताया जायेगा कि कैसे इस पैसे को खर्च करें । मैंने एक इंजीनियर से पूछा है । उसने मुझे बताया है कि दो डिविजन के बजाय अगर छः डिविजन लगा दिये जायें, जो रेट्स हैं उनको बदल दें, सिमेंट मिल जाये और कांट्रेक्टर को समय पर पेमेंट हो जाये, जल्दी उसको पेमेंट कर दिया जाये और जो खुदाई का काम है वह गांव वालों के जिम्मे कर दिया जाये और वे इसको जल्दी करें तो काम काफी आसानी से और तेजी से आगे बढ़ सकता है । लेकिन अभी तक प्लानिंग कमीशन से ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सिंचाई विभाग को आश्वासन नहीं मिला है कि रुपया दिया जायेगा और वह रुपया इनकी मार्फत बिहार सरकार को जायेगा । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के दोनों मंत्री यहां बैठे हुए हैं । एक विशेषज्ञ हैं और दूसरे राजनीतिज्ञ हैं दोनों का सम्मिलन होने से मैं समझता हूं कि गंडक योजना का जो काम है वह शीघ्रातिशीघ्र चालू हो जायेगा ।

इससे फायदा क्या होगा यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं । अगर इसको पहले पूरा कर दिया गया होता तो इससे फसलों की पैदावार में दो करोड़ पचास लाख मन की वृद्धि हो गई होती जिसमें एक करोड़ बीस लाख मन खाद्यान्न हैं और एक करोड़ तीस लाख मन पटसन है । आज जूट का दाम हमारे जिले में 65 रुपया है । हो सकता है कि कलकत्ता में वह ज्यादा हो । जिस जमाने में यह बीस करोड़ रुपये की पैदावार होने वाली थी उस समय इस योजना का कुल तखमीना खर्च का, 36 करोड़ रुपया था । अब आप देख लें कि इतनी हमारी पैदावार मारी गई है । आप यह भी देखें कि इससे 32 लाख एकड़ जमीन पटने वाली है । उस जमीन से बीस करोड़ की आमदनी होने वाली थी । अब आमदनी का तखमीना भी कुछ अधिक हो जायेगा । यह जो स्कीम आपकी है इस स्कीम से बढ़िया और कोई हिन्दुस्तान में स्कीम नहीं है । फिर भी न जाने हमारी केन्द्रीय सरकार इस पर क्यों गम्भीरता से विचार नहीं करती है ।

केन्द्रीय मंत्रियों ने और विशेषज्ञों ने और जितने इस विभाग के आदमी आये उन्होंने भी कहा कि जब तक इस स्कीम को केन्द्र अपने हाथ में नहीं लेता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकती है, इसकी रफ्तार तेज नहीं हो सकती है । ऐसा जो कहा गया इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इस स्कीम से तीन राज्यों का सम्बन्ध है । एक तो नेपाल राज्य है, दूसरे बिहार राज्य का सम्बन्ध है और तीसरे उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है । यदि केन्द्रीय सरकार इस योजना को अपने हाथ में ले लेती तो इस योजना के सफलीभूत होने में ज्यादा

[श्री विभूति मिश्र]

देर न लगती। इसका कारण यह है कि नेपाल को अगर बिहार सरकार कोई पत्र लिखना चाहती है तो वह पहले उस पत्र को केन्द्र के पास भेजेगी और केन्द्र उसको नेपाल सरकार के पास भेजेगा और जब नेपाल से उसका जवाब आयेगा तो वह पहले केन्द्र के पास आयेगा और फिर बिहार के पास जायेगा। यही बात तब पैदा होगी अगर उत्तर प्रदेश नेपाल को पत्र लिखना चाहेगा। ये सब कारण हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये और इस योजना को जल्दी समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये।

आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि गंडक योजना का जो बैरेज है वह बैरेज अगले साल निश्चित रूप से कम्प्लीट हो जायेगा। बैरेज के साथ साथ जहां से उत्तर प्रदेश और सारन के लिए कैनाल निकलेगी वहां साठ मील में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसी तरह से ईस्टर्न साइड में जहां चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में लाइन जाने वाली है कैनाल की, वहां भी तीस मील में खुदाई नहीं हुई है। उसके लिए कहा जाता है कि इनके पास मशीनरी नहीं है। जो सख्त मिट्टी है, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उसकी खुदाई के लिए कहा जाता है कि इनके पास मशीनरी नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सदन में यह आश्वासन दें कि इस योजना के लिये चौथी योजना में काफी धन रखा जायेगा और इसको चौथी योजना के काल में अवश्य समाप्त भी कर दिया जायेगा। हमारा जो हिसाब है उस हिसाब के मुताबिक तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जा कर यह योजना पूरी होगी। मैं चाहता हूं कि चौथी योजनाकाल में मंत्री महोदय इसको पूरा करने का आज स्पष्ट आश्वासन दें।

हमारे थैकर साहब वहां गए थे। वह बड़े सज्जन हैं। मैं अशोक मेहता साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों की मदद की है। जब बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि 56 करोड़ रुपया खर्च कर दस लाख एकड़ जमीन चौथी योजना के अन्त तक पटा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हम आठ करोड़ रुपया और देते हैं और आप छः लाख एकड़ और जमीन पटा दो। इस तरह से सोलह लाख एकड़ भूमि पट जाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि जो एजेंसी वहां बनी है उस एजेंसी में कैपेसेटी नहीं है कि इतने पैसे को खर्च कर सके। काम जल्दी हो, इसके लिए जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार इसमें मदद करे, अपनी तरफ से वह इंजीनियर दे, अपनी तरफ से काम करें। तभी काम हो सकता है। जब तक केन्द्रीय सरकार का सहयोग नहीं होगा तब तक जो संगठन वहां बनाया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, उससे इतना काम नहीं होने वाला है।

जो बैरज का काम है वह पब्लिक सैक्टर में जो नैशनल प्राजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन है, उसके सुपुर्द किया गया है। उसको पहले सभी खराब कहते थे। लेकिन उसने वहां पर काबिले तारीफ काम किया है। उसके काम को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल बैरेज कम्प्लीट हो जाएगा। बैरेज के साथ साथ जो कैनाल्ज खुदने वाली है उन पर एक सौ नौ पुल बनेंगे। इन 109 पुलों में से तीन पुल ही कम्प्लीट हुए हैं और छः पुल ऐसे हैं जिन पर आधा काम हुआ है, चौथाई काम हुआ है। सौ पुलों पर कोई काम नहीं हुआ है, उन पर हाथ भी नहीं लगा है। इतनी लाभकारी योजना को इतने गैर तसल्लीबख्श तरीके से पूरा किया जा रहा है। जो रुपया खर्च हो चुका है अगर

उसको फेंकना चाहते हैं आप मिट्टी में तो आप की इच्छा, नहीं तो जो आजकल उसकी स्थिति है उसको देखते हुए आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का प्रयत्न करें, इसके लिए आप पैसा दें, इसके लिए साधन दें, इसके लिए मशीनरी दें।

Shri K. N. Pande (Hata): I want to put a question.

Mr. Chairman: The hon. Member is a very old Parliamentarian. He must know the rules. If he wanted to put a question, he must have given notice of it before the discussion began. He has not given his name.

Shri K. N. Pande: That is true. Can I not make a request now?

Mr. Chairman: No. He must know the rules. He is an old Parliamentarian.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैंने नोटिस दिया था और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि गंडक योजना जिस समय प्रारम्भ की गई थी उस समय इस पर कितनी धन राशि खर्च करने का विचार था? क्या यह सच है कि अब वह सौ करोड़ से भी ऊपर जा पहुंची है? यदि हां तो इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या यह योजना विदेशी सहायता से पूरी की जा रही है? यदि हां तो चूंकि विदेशी सहायता नहीं मिल रही है, क्या यह सही है कि इस कारण से इसको पूरा नहीं किया जा रहा है?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : जो कुछ खयालात हमारे सामने रखे गए हैं उनसे मैं बिल्कुल मुत्तफक हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारी कोशिश यह है कि हिन्दुस्तान में जितने भी वाटर रिसोर्सिस हैं उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करके हम अपनी फूडप्रोडक्शन को बढ़ावें। इसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशल लिमिटेशंज हमारे रास्ते में हैं और उनकी वजह से जो कुछ काम हम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं।

मैं यह बात भी मानने के लिये तैयार हूं कि गंडक प्रोजेक्ट बिहार सूबे के लिये बहुत जरूरी है।

Shri K. N. Pande: Not only Bihar but U.P. also. We have been ruined. And this House is going to establish a new practice that I cannot even put a question because that is the ruling of the Chair.

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member must know the rules. He has been a Member of this House for long enough, and it is rightly expected that he should take the trouble of going through the rules. I shall not allow him to do anything which is beyond the rules.

श्री हुकम चन्द कछवाय: सभापति महोदय, आप का अपमान किया जा रहा है, यह बहुत खेदजनक बात है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें।

श्री फखरुद्दीन अहमद : बिहार और यू० पी० दोनों ही के लिये यह बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, और इसके बन जाने से मैं जानता हूं कि दोनों सूबों में ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकता है और इस वक्त जो हमारी फूड की समस्या है उसमें बहुत दूर तक मदद पहुंच सकती है। इसीलिये यह प्रोजेक्ट लिया गया। जिस वक्त यह लिया गया था उस वक्त यह खयाल था कि 1961 में इस पर 54 करोड़ रुपया खर्च होगा। 37 करोड़ रुपया बिहार का और 17 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : राजस्थान में कितना होगा।

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह प्रोजेक्ट राजस्थान के लिये नहीं है ।

अभी जो एस्टिमेट है उससे मालूम होता है कि इस प्रोजेक्ट पर, इसके खत्म होने तक 121 करोड़ रु० तक खर्च हो सकता है हमारी इच्छा है कि यह प्रोजेक्ट जितना जल्दी पूरा हो उतना अच्छा है क्योंकि जितनी देर होती है उतनी ही इसकी कीमत में और खर्च में ज्यादती होगी और हमको रुपया निकालने की सूरत निकालनी पड़ेगी ।

इस वक्त मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि चन्द महीने हुए मैंने खुद गंडक प्रोजेक्ट को देखा, और देख कर मुझे इत्मीनान हुआ कि बैराज का काम बहुत अच्छी तरह हो रहा था । इस साल के शुरू में बिहार गवर्नमेंट और यू० पी० गवर्नमेंट ने जो जो रुपया उनके बजट में इस प्रोजेक्ट के लिये होना चाहिये था उसका एस्टिमेट भेजा था । बिहार गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिये हमें इस साल के लिये उनको 9.18 करोड़ रुपया देना चाहिये । लेकिन इस वक्त रुपये की कमी की वजह से सिर्फ 2 करोड़ रुपये की मंजूरी यहां से हुई थी, और यह कहा गया था कि 1 करोड़ रुपया उस जगह खर्च किया जायेगा जो कि नेपाल टेरिटरी में है । लेकिन कम देने के बाद बिहार और यू० पी० गवर्नमेंट्स की तरफ से जब हमारे एस्टिमेट्स आये कि और ज्यादा रुपया दिया जाना चाहिये, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त हमने बिहार गवर्नमेंट को 7 करोड़ रुपया देने का और यू० पी० गवर्नमेंट को ३.७ करोड़ रुपया देने का इन्तजाम किया । इसके अलावा एक करोड़ रुपया नेपाल की टेरिटरी में खर्च होगा । अगर इन तमाम रुपयों को जोड़ा जाये तो करीब 8 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है जब कि मांग इस साल के लिये 9 करोड़ से कुछ ज्यादा की थी । मैं आपसे यह भी कह देना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि किस कदर कमी हो रही है । अगर कमी की वजह से रुपये की जरूरत होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जो रुपया हम मुहैया करें उसमें जितनी कमी हो सके उतनी हो ।

इसके अलावा शायद आपको यह भी मालूम हो कि हमारी यह कोशिश है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पूरा होने में इस वजह से दिक्कत होती है कि हम उनको स्टेट प्लैन में रखते हैं और स्टेट प्लैन में रिसोर्सेज कम होने की वजह से बहुत सी जगहों में रुपया नहीं मिल सकता है, उन को हम अपने हाथ में लें । हम चाहते हैं कि जो आठ या नौ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ले । इसकी बाबत हम प्लानिंग कमिशन से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करेंगे । जहां तक मेरे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि इस पालिसी के साथ हमारी पार्लियामेंट भी है कि हम कोशिश करें कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनको रिसोर्सेज की दिक्कत की वजह से स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, या टेक्निकल नो हाऊ की वजह से वह नहीं कर सकती, हम उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर जल्दी से जल्दी खत्म करें ।

Shri Basappa (Tiptur): Upper Krishna Project in Mysore also.

श्री फखरुद्दीन अहमद : मैं इस वक्त यह नहीं कहना चाहता कि कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आठ या नौ प्रोजेक्ट्स हम सारे देश में लेना चाहते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बाबत हमको प्लानिंग कमिशन से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से रुपया मिलेगा और इस पालिसी पर जल्दी अमल करने की हम कोशिश करेंगे । ऐसा करने से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रोजेक्ट्स जिनमें काफी देर रिसोर्सेज की कमी की वजह से हुई है खत्म हो जायेंगी और यह काम करके हम जल्दी से जल्दी अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : गंडक प्रोजेक्ट्स के के बारे में तो बतलाइये ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : गंडक इसमें शामिल है ।

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): As regards the question put by Shri Kachhavaiya—he asked why the estimate of the project has gone up from Rs. 53 crores to Rs. 121 crores —the answer must come from the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra, himself. He is going on increasing the cost there. The main reason is this. Originally these canals were supposed to take up to 5 cusecs. Later on it has been decided to take upto 2 cusecs. That has caused nearly 10—15 per cent extra rise in cost. Also the original area was about 28 lakh acres. Now it has been further extended. The hon. Member goes on adding acres after acres. So many lakhs of acres have been added. This has enlarged the scope of the project. Naturally, that has to come out of money. Therefore, there is a rise in cost.

All these things are gone into very carefully by a technical committee. Every effort is being made to review the cost. Nevertheless, I do not think the cost will come down below the figure generally estimated. The endeavour is, as the hon. Minister has said, to try to complete the scheme along with other important ones in the country as early as possible.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैंने एक बहुत छोटी सी बात पूछी थी कि क्या यह विदेशी सहायता से बनाई जा रही है ।

Dr. K. L. Rao: I am sorry I forgot it. There is no question of foreign collaboration in this. It is a very simple work. Even if it were a difficult work, Indian talent has come to that stage when we can tackle it ourselves. Therefore, there is no question of foreign collaboration, much less any kind of fear about the project not being handled properly; the whole project is being handled by purely Indian talent.

Shri Bhagwat Jha Azad: Some amount for invisible expenditure and for administration must also be there.

17.28 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 29, 1966/Sravana 7, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS II—1015 (ai) LS—4-10-66—970